फ़रवरी , 2023, वर्ष : 44 अंक : 02

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्यांग पेंपा छेरिंग।

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

फ़रवरी, 2023, वर्ष : 44 अंक : 02

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

भारतीय कॉलेज छात्रों और एम३एम फाउंडेशन के सदस्यों के साथ परम पवन दलाई लामा।

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन, ताशी देकि

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- एम३एम फाउंडेशन से आए आगंतुकों के लिए प्रवचन 1
- तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्यों के लिए सहायता 2
- १६वें कशाग के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बतियों को तिब्बती नववर्ष- लोसार २१५० पर बधाई दी 3
- संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चीन द्वारा तिब्बत में १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने और अलग रखने के प्रति चेताया 4
- सिक्योंग ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, तिब्बत बिल को लागू करने में समर्थन मांगा 5
- चीनी अधिकारियों ने ड्रैगो काउंटी में तिब्बतियों पर संचार प्रतिबंध लगाया 6
- बीजिंग तिब्बत में अवज्ञा के किसी भी संकेत को अलगाववाद के कृत्य के रूप में देखता है और उसे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताता है। लिथांग काउंटी में हिरासत में राजनीतिक कैदी गेशे फेंडे ग्यालत्सेन की मौत 7
- एनएचआरसी के ५२वां सत्र शुरू होने पर तिब्बत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ तिब्बतियों का प्रदर्शन 8
- प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने विदेश, रक्षा, व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के सदस्यों से मुलाकात की 9
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में 'तिब्बत-चीन संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने' के लिए तिब्बत विधेयक को फिर से पेश किए जाने का स्वागत किया 10
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती रिनचेन ल्हामो ने सीटीए का दौरा किया 11

समाचार -

- सिक्योंग वाशिंगटन डीसी में एमेरिटस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सांसद जिम मैकगवर्न से मिले 12
- जापान के तिब्बत समर्थक समूह ने चीन को तिब्बती धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी 13
- तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह ने १० लाख तिब्बतियों को जबरन आत्मसात करने और अलग करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चिंता से सहमति जताई 14
- चीन की प्रतिबंधात्मक नीतियां तिब्बत में लगातार जारी है 15
- संयुक्त राष्ट्र समिति का तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में एकत्ववादी नीतियों और व्यापक अधिकारों के उल्लंघन पर चीन से सवाल 16
- यूरोपीय संघ ने तिब्बती राजनीतिक कैदियों की अविलंब रिहाई की मांग की 17
- दस लाख तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से जबरन अलग किया गया : संयुक्त राष्ट्र 18
- स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल ने स्पेनिश सांसदों द्वारा 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' के गठन पर आभार व्यक्त किया 19
- स्पेनिश सीनेट में तिब्बत के लिए पहला अंतर-संसदीय समूह गठित 20
- भारत के माननीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में समयलिंग बस्ती में लोसार समारोह की अध्यक्षता की 21
- बीटीएसएम की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गाजियाबाद के कैलाश-मानसरोवर भवन में संपन्न 22
- चीन ने तिब्बती नववर्ष समारोह में बौद्ध ध्वज फहराने पर रोक लगाई, आयोजक को हिरासत में लिया और जुर्माना लगाया 23

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

24
- चीन ने तिब्बती नववर्ष समारोह में बौद्ध ध्वज फहराने पर रोक लगाई, आयोजक को हिरासत में लिया और जुर्माना लगाया

अपनी बात

❖ चीनी आत्मसात नीति से अलगाव के शिकार होते तिब्बती बच्चे

तिब्बत का षड्यंत्रपूर्वक चीनीकरण अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिये गंभीर चिन्ता का विषय है। तिब्बती मूल्य बौद्ध दर्शन पर आधारित हैं। चीनीकरण को नहीं रोका गया तो संपूर्ण विश्व को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि प्राचीन भारतीय बौद्ध नालंदा परंपरा में निहित मानवीय मूल्य संपूर्ण विश्व के लिये कल्याणकारी हैं। चीन सरकार इन्हीं आदर्शों को मिटाकर तिब्बती पहचान मिटाने में लगी है। शांति, अहिंसा, करुणा और पारस्परिक सद्भावपूर्ण सहयोग जैसे मानवीय मूल्य ही तिब्बती मूल्य तथा तिब्बती पहचान हैं। साम्राज्यवादी चीन सरकार की अनेक योजनायें इन्हीं मूल्यों और पहचान को समाप्त करने हेतु तिब्बत में लागू की गई हैं। तिब्बत में लागू चीन सरकार की ''एसिमिलेशन पॉलिसी'' अर्थात् आत्मसात-नीति इसी का नया उदाहरण है।

आत्मसात-नीति के अन्तर्गत चीन सरकार द्वारा तिब्बत में छः से पन्द्रह साल के छोटे बच्चों को आवासीय विद्यालयों में रखा जा रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग दस लाख है। ये बच्चे पूरी तरह अपने परिजनों, तिब्बती भाषा तथा कल्याणकारी जीवन दर्शन एवं सांस्कृतिक मूल्यों से अलग हो गये हैं। तिब्बती लोगों की इच्छा के विरूद्ध उनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। चीन सरकार आवासीय विद्यालयों में उन बच्चों का चीनीकरण कर रही है। इसी को एसिमिलेशन कहा जा रहा है, जबकि वास्तव में यह ''एसिमिलेशन पॉलिसी'' अर्थात् अलगाव नीति है। इन तिब्बती बच्चों का तिब्बत से अलगाव हो रहा है। वे चीनी परंपरा को आत्मसात कर रहे हैं। तिब्बती बच्चों में यह तथाकथित एसिमिलेषन पॉलिसी पूरी तरह अस्वीकार्य है।

चीन सरकार तिब्बतियों का जबरन डी.एन.ए. जमा कर रही है। किसी विशेष परिस्थिति में अत्यावष्यक होने पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति का डी.एन.ए. परीक्षण किया जाता है। तिब्बत में ऐसे किसी भी कानून का पालन किये बिना तिब्बतियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन घोर चिंता का प्रशन है। चीन सरकार की इस नीति का उदेश भी तिब्बत का चीनीकरण है। चीन सरकार 1959 से ही तिब्बती पहचान मिटाने में लगी है। बौद्ध मठ-मंदिर, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक-ऐतिहासिक अवशेष नष्ट और विकृत किये जा रहे हैं। भगवान् बुद्ध के अनुयायियों को प्रताड़ित-पीड़ित किया जा रहा है। बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों की जबर्दस्ती नसबंदी हो रही है। ये समस्त उदाहरण तिब्बत में बिगड़ती जा रही आंतरिक स्थिति के प्रमाण हैं।

मार्क्स, लेनिन और माओत्सेतुंग के साम्यवादी दर्शन को मानने वाली चीन सरकार तिब्बतियों के बौद्ध परंपराओं में भी अवांछित हस्तक्षेप कर रही है जबकि साम्यवाद धर्म को अफीम या जहर समझता है। ऐसे में यह प्रशन स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं में चीनी हस्तक्षेप का कारण क्या है? उत्तर स्पष्ट है। अपने हस्तक्षेप द्वारा चीन सरकार तिब्बत की सुस्थापित एवं सुव्यवस्थित धार्मिक परंपराओं को विकृत करना चाहती है। दलाई लामा, पंचेन लामा, टुल्कू एवं रिंपोछे आदि पद अतिसम्मानित पद हैं। इन पर व्यक्तियों का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर तिब्बती धर्मगुरुओं तथा बौद्ध विद्वानों द्वारा किया जाता है। वर्तमान परम पावन दलाई लामा का चयन भी इसी प्रकार हुआ था। पुनर्जन्म और अवतार संबंधी बौद्ध परंपरा बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित है। चीन सरकार, जो साम्यवादी होने के कारण पुनर्जन्म और अवतार के विचार को अनुचित मानती है, दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म के संबंध में स्वयं निर्णय लेने को तैयार है। चीन सरकार का ऐसा कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं होगा। पुनर्जन्म और अवतार संबंधी निर्णय तिब्बती धर्मगुरु और बौद्ध विद्वान ही करेंगे। उनका निर्णय ही स्वीकार्य और प्रभावी होगा।

तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कर चुका चीन तिब्बती आकांक्षाओं तथा मूल्यों को प्रकाशित -प्रचारित-प्रसारित करने वाले तिब्बती विद्वानों, कलाकारों, पत्रकारों, लेखकों, शिक्षकों तथा धर्मगुरुओं की अवैध गिरफ्तारी कर रहा है। उन्हें क्रूरतापूर्ण यंत्रणायें दे रहा है। वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिंपिंग इस मामले में और अधिक अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। उनके शासनकाल में तिब्बत में मानवाधिकार हनन, प्राकृतिक संपदा का विनाश तथा पर्यावरण-प्रदूषण साजिषपूर्वक व्यापक पैमाने पर जारी है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में तथा मानवाधिकार संबंधी अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट में तिब्बत की आंतरिक दषा को अत्यन्त गंभीर बताया जा रहा है। उनके अनुसार चीनी पराधीनता के शिकार तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति सीरिया और नॉर्थ कोरिया में मानवाधिकार के समान हो गई है। विष्व में मानवाधिकार की सर्वाधिक खराब स्थिति के उदाहरण में सीरिया और नार्थ कोरिया के साथ तिब्बत का नाम जुड़ जाना अत्यन्त चिंता का विषय है।

विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों से तिब्बती समुदाय की अपेक्षा है कि वे तिब्बत में जारी चीनीकरण, मानवाधिकार हनन, प्राकृतिक संसाधनों के विनाश तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये चीन सरकार को बाध्य करेंगे। परमपावन दलाई लामा तथा तिब्बती समुदाय द्वारा मतदान के माध्यम से निर्वाचित तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ चीन सरकार पुनः वार्ता प्रारंभ करे। दलाई लामा एवं निर्वासित तिब्बत सरकार पूर्ण आजादी की जगह चीन के अन्तर्गत सिर्फ ''वास्तविक स्वायत्तता'' लेने को तैयार हैं। चीन सरकार अपने पास वैदेशिक मामले और प्रतिरक्षा विभाग रखे। कृषि, उद्योग समेत अन्य सभी विषय वह तिब्बतियों को सौंप दे। इससे चीन की एकता-अखंडता एवं संप्रभुता सुरक्षित रहेगी तथा तिब्बतियों को स्वषासन का अधिकार मिलेगा। यही मध्यममार्ग है अर्थात् बीच का रास्ता। ऐसी व्यवस्था चीन के संविधान तथा उसके राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अनुकूल होगी। तिब्बत संकट का व्यावहारिक हल यही है।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान)
मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

▶ एम३एम फाउंडेशन से आए आगंतुकों के लिए प्रवचन

Dalailama.com, २८ फरवरी, २०२३

थेगछेन छोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज २८ फरवरी की प्रातः परम पावन दलाई लामा ने अपने आवास से सटे मुख्य तिब्बती मंदिर छुगलगखंग के प्रांगण में हाल ही में स्नातक हुए १२० भारतीय कॉलेज छात्रों और एम३एम फाउंडेशन के सदस्यों का अभिनंदन किया।'एम३एम इंडिया' समूह द्वारा स्थापित 'एम३एम फाउंडेशन' उज्जवल भारत बनाने के लिए एकसमान विकास सुनिश्चित पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके सतत विकास करना और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। फाउंडेशन अपनी देखरेख में छात्रों में जीवन कौशल को बढ़ावा देता है। उन्हें समानता, सहानुभूति, समावेश, सहयोग और विश्वास को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

परम पावन ने जब अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब एम३एम के अध्यक्ष ने उन्हें टोपी और शॉल भेंट करते हुए पारंपरिक हिमाचली स्वागत किया। पांच गायों को बछड़ों के साथ पास में बंधे होने की ओर संकेत देते हुए उन्होंने परम पावन को सूचित किया कि इनमें से चार गायें चार विधवाओं को और एक गाय स्थानीय स्कूल को दी जानी हैं। सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर परम पावन ने प्रवचन शुरू किया :

'मनुष्य के रूप में हम सभी भाई-बहन हैं। लेकिन इसके अलावा हम तिब्बतियों के भारत के साथ लंबे समय से विशेष संबंध रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'सातवीं शताब्दी में तिब्बती राजा छोंगत्सेन गम्पो ने एक चीनी राजकुमारी से शादी की और मुझे यकीन है कि उन्हें चीनी भोजन बहुत पसंद आया। हालांकि, एक बार जब उन्होंने यह तय कर लिया कि तिब्बतियों को अलग लिपि की जरूरत है, तो उन्होंने चीनी वर्णों की बजाय भारतीय देवनागरी वर्णमाला पर आधारित नई तिब्बती लिपि तैयार करवाई।

'एक शताब्दी बाद एक अन्य तिब्बती राजा ठिसोंग देचेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के अग्रणी विद्वानों में से एक आचार्य शांतरक्षित को तिब्बत आमंत्रित किया। शांतरक्षित ने अपने बौद्ध-धर्म के विशाल ज्ञान का परिचय दिया, जिसमें छोटे से छोटे कण से लेकर अंतरिक्ष और चित्त के कार्यकलापों तक- सब कुछ की समझ शामिल थी।'

परम पावन ने कहा, 'कभी-कभी मैं मज़ाक में कहता हूं कि अतीत में हम तिब्बती चेला थे और आप भारतीय गुरु थे। पर जब भारतीय लोग पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर उसके अधिक निकट आ गए, तो हम तिब्बतियों ने ही प्राचीन भारतीय ज्ञान और मूल्यों को संजोकर रखा है। अनिवार्य रूप से इसमें करुणा और अहिंसा का मूल्य शामिल है। ध्यान रहे, यद्यपि हम करुणा और अहिंसा को महत्व देते हैं, इसलिए हम तिब्बती शक्तिशाली और मजबूत बने हुए हैं। करुणा आंतरिक शक्ति लाती है जिससे आंतरिक शांति, अधिक आत्मविश्वास और मुस्कुराने की क्षमता आती है। यह इसलिए है क्योंकि मैं करुणा की साधना करता हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा, इसीलिए 'मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं।'

परम पावन ने आगे समझाया कि एक दार्शनिक और तर्कशास्त्री के रूप में आचार्य शांतरक्षित का बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण कारण और तर्क की क्रमिक समझ विकसित करने पर आधारित था। उसी समय तिब्बत में चीनी भिक्षु शिक्षा दे रहे थे कि शांत ध्यान अधिक प्रभावी दृष्टिकोण है। राजा ठिसोंग देचेन ने चीनी भिक्षु हशांग और शांतरक्षित के शिष्य कमलशील के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन कराया। इस शास्त्रार्थ में भारतीय विद्वान को विजेता घोषित करते हुए उन्होंने उनकी अध्ययनशील, शोधपरक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को स्वीकृति प्रदान की। परम पावन ने उल्लेख किया कि उन्होंने केवल चार या पांच वर्ष की आयु में चित्त और भावनाओं के कार्य के बारे में सीखना प्रारंभ किया तो उनका लालन-पालन भी इसी दृष्टिकोण के तहत हुआ था।

उन्होंने कहा, 'जब से मैं भारत में रहने आया हूं, मैं उन सभी विद्वानों और वैज्ञानिकों सहित सभी प्रकार के लोगों से मिलता-जुलता रहा हूं, जो चित्त की शांति प्राप्त करने की विधियों में रुचि रखते हैं। जिन्हें हमने जीवित रखा है। मुझे विश्वास है कि यदि हम दिमाग की बेहतर समझ के साथ तकनीकी विकास को जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम उचित, स्वस्थ तरीके से प्रौद्योगिकी को नियोजित करने में भी सक्षम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अत्याधुनिक और परिष्कृत हथियारों के विकास में तकनीकी कौशल का उपयोग करना गलत है। विज्ञान का बेहतर उपयोग शांति की खोज में किया जाना चाहिए।

'आज जीवित सभी आठ अरब मनुष्य शांति से रहना चाहते हैं। स्नेहशील होना मानव का मूल स्वभाव है। जब हम पैदा होते हैं तब हम अपनी मां की गोद और देखभाल के तहत रहते हैं और शांति पाते हैं। फिर, बचपन में हम दूसरों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हम अपने बीच विभेदों की पहचान नहीं करते हैं। इस तरह का भेदभाव करना हम बाद में सीखते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। स्कूल का माहौल हमें 'हम' और 'उन' के आधार पर भेदभाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है।'

'चूँकि हम सभी मनुष्य हैं, हमें एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में देखने की आवश्यकता है। लड़ने और मारने के लिए हथियारों पर निर्भर रहने से विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलता। धर्म के नाम पर लड़ना विशेष रूप से दुखद है, क्योंकि सभी धर्म अपने मूल में करुणा और प्रेम-कृपा ही सिखाते हैं।'

'यदि हम मानवता की एकता के संदर्भ में सोचते हैं तो हम हथियारों से दूर हो सकते हैं और अपने बीच किसी भी मतभेद को बातचीत और चर्चा के माध्यम से हल कर सकते हैं। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हमारे

पास क्या समान है। हम सभी एक ही तरह से पैदा हुए हैं और हम सभी एक ही तरह से मरते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवनकाल में हम हथियारों और हिंसक संघर्षों से मुक्त एक वास्तविक शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं।'

'अधिक क्या कहना। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी गंभीर होती जा रही है, इसीलिए जब तक हम कर सकते हैं, हमें एक-दूसरे की मदद करते हुए एक साथ खुशी से रहना सीखना चाहिए।'

श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में परम पावन ने इस बात की सराहना की कि भारत में कितने विविध रीति-रिवाज और दृष्टिकोण साथ-साथ फलते-फूलते हैं। जो लोग इस विविधता को स्वीकार करते हैं, वे शांतिपूर्वक एकसाथ रहते हैं। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसी बातें हैं, जिसे दुनिया सीख सकती है।

उन्होंने छोटे बच्चों को 'मैं' भाव को कम और 'हम' भाव को अधिक आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम जिन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका मतलब है कि हमें सहयोग करना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। 'हम' और 'वे' के विचार पुराने हो चुके हैं।

अंत में, यह पूछे जाने पर कि आध्यात्मिक विकास कैसे प्राप्त किया जाए, परम पावन ने कहा:

'हमारे मन को कई अलग-अलग भावनाएं प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ क्रोध और भय जैसी भावनाएं परेशान करने वाली होती हैं, जबकि सहानुभूति और करुणा जैसी कुछ अन्य भावनाएं आनंद प्रदान करती हैं। सकारात्मक भावनाओं का पोषण स्वाभाविक रूप से विनाशकारी भावनाओं को कम करने में मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह करुणा ही है जो आंतरिक शक्ति और मन की शांति की ओर ले जाती है। इसलिए, हमें अपने आप को लगातार याद दिलाना है कि एक ही मानव परिवार के सदस्य के रूप में हम भाई-बहन हैं। और हमें उन अच्छे लोगों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जो शांति के लिए काम करते हैं न कि वैसे लोगों का, जो लड़ते और मारते हैं।'

जब वह अपने आवास जाने लगे तो गोल्फ-कार्ट में चढ़ते से पहले परम पावन उन गायों का निरीक्षण करने के लिए रुके, जिनको दान के रूप में दिया जानेवाला था। उन्हें देखकर परम पावन ने उनके प्रति कुछ दयापूर्ण शब्द कहे।

▶ तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्यों के लिए सहायता

dalailama.com, ०७ फरवरी, २०२३

थेगछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंपों की खबरों से दुखी होकर परम पावन दलाई लामा ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखा है। इस भूकंप से व्यापक जनहानि हुई और कई लोग घायल हुए हैं।

परम पावन ने लिखा, 'मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं।'

'साथ ही, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के समन्वित स्वास्थ्य टीमों के अलावा गैर सरकारी संगठन और दुनिया भर के कई देश भूकंप क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में सहायता भेज रहे हैं।'

'इस त्रासदी से प्रभावित तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के प्रतीक के रूप में, मैंने 'गादेन फोडरंग फाउंडेशन ऑफ दलाई लामा' से राहत और बचाव कार्यों के लिए दान करने के लिए कहा है।'

▶ १६वें कशाग के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बतियों को तिब्बती नववर्ष- लोसार २१५० पर बधाई दी

tibet.net, २० फरवरी, २०२३

धर्मशाला। १६वें कशाग के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने पारंपरिक तिब्बती नव वर्ष-जल-खरगोश का वर्ष 'लोसार-२१५०' के अवसर पर तिब्बत के अंदर और बाहर के तिब्बतियों को बधाई दी। तिब्बती नव वर्ष २१ फरवरी २०२३ से शुरू हो रहा है।

सिक्योंग का संदेश:

तिब्बती कैलेंडर के २१५०वें वर्ष के शुरू होने के अवसर पर, जो कि वाटर हेयर ईयर (जल-खरगोश का वर्ष) भी है, परम पावन दलाई लामा को श्रद्धासुमन अर्पित करने से पहले मैं १६वें कशाग की ओर से और व्यक्तिगत रूप से तिब्बत के अंदर और तिब्बत के बाहर के सभी तिब्बतियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस अवसर पर हम एक नई उम्मीद के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं।

यह आशा रखने के लिए बेशक पहले हमें अपनी स्थिति को समझना होगा। आज जो हम यहां जीवित हैं, वह मुख्य रूप से परम पावन के नेतृत्व के कारण, परम पावन की दूरदर्शी दृष्टि के कारण और पिछले ६३ वर्षों में, जब से हम निर्वासन में आए हैं, परम पावन के सभी कार्यों के कारण जीवित हैं। परम पावन हाथ जोड़कर दुनिया भर में घूम रहे हैं और यही कारण है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, वहां हैं। इसलिए, मैं प्रत्येक तिब्बती से आग्रह करता हूं कि वे परम पावन द्वारा की गई सेवाओं को पहचानें और परम पावन

के मार्गदर्शन का पालन करें, क्योंकि परम पावन एक ऐसे नेता हैं जिनका दुनिया में सभी सम्मान करते हैं।

परम पावन ने भी अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता और विशेष रूप से हम तिब्बतियों के लाभ के लिए लंबा जीवन जीने की इच्छा के बारे में कई बार आश्वासन दिए हैं। इसलिए, लामा लंबे समय तक जीवित रहते हैं या नहीं यह भी लामा और शिष्यों के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। और उनका शिष्य होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उनके मार्गदर्शन का पालन करें और हम हर गतिविधि पर उनके नेतृत्व, उनके शब्दों और उनके विचारों का पालन करें। चाहे वह चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के बारे में हो या चाहे वह तिब्बतियों के कल्याण के बारे में हों। ये दो जिम्मेदारियां निर्वासन में तिब्बती समुदाय की ओर से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को सौंपी गई हैं।
हम परम पावन दलाई लामा के विचारों और उनके द्वारा कई वर्षों से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी तिब्बतियों से भी इसका पालन करने का आग्रह करता हूं और हम सभी तिब्बतियों के सहयोगात्मक प्रयास से वह हासिल करने में सक्षम होंगे। चाहे वह तिब्बत के अंदर ७० लाख तिब्बती हों या निर्वासन में १,३०,००० तिब्बती।

हमारा एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व है और इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम सभी तिब्बत के मुद्दे में योगदान करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, जिन्हें हमने निर्धारित किया है।

मैं फिर से आपको तिब्बती नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी हों, ताकि इस वर्ष के दौरान आप बीमार महसूस न करें और समुदाय की सेवा करने की स्थिति में रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर से लोसार की शुभकामनाएं!

▶ संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चीन द्वारा तिब्बत में १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने और अलग रखने के प्रति चेताया

tibet.net, ०६ फरवरी, २०२३

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह ने ०६ फरवरी को कड़े शब्दों में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों में १० लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करने और तिब्बती संस्कृति को आत्मसात करने की नीति के लिए चीन की कड़ी निंदा की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए चीनी सरकार के साथ हुई अपनी बातचीत सार्वजनिक की थी।
प्रेस विज्ञप्ति में अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टियर श्री फर्नांड डी. वारेनस, शिक्षा के अधिकार पर विशेष दूत सुश्री फरीदा शाहीद और सांस्कृतिक अधिकार मामले की विशेष दूत सुश्री एलेक्जेंड्रा ज़ांथकी ने संयुक्त रूप से 'आवासीय विद्यालय प्रणाली के माध्यम से तिब्बती लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप से आत्मसात करने' के उद्देश्य से लागू चीनी नीतियों पर चिंता व्यक्त की। विशेषज्ञों ने चेताया कि करीब दस लाख तिब्बती बच्चे इस नीति से प्रभावित हुए हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि वे 'तिब्बती बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रणाली' से परेशान हैं, जो हाल के वर्षों में तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में विलीन करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने के कार्यक्रम चलाता हुआ प्रतीत होता है।

चीन के अधीन तिब्बत के बच्चों को तिब्बती भाषा, इतिहास और संस्कृति की जगह मंदारिन भाषा में अनिवार्य शिक्षा देने के पाठ्यक्रम का वर्णन करते हुए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा, 'इसका परिणाम यह हुआ है कि तिब्बती बच्चे अपनी मूल भाषा से अनभिज्ञ हो रहे हैं। तिब्बती भाषा में अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ आसानी से बात करने की उनकी क्षमता नष्ट हो रही है और इससे उनकी पहचान पर संकट मंडरा रहा है जो उन्हें हान संस्कृति में विलीन होने की ओर ले जाता है।

विशेषज्ञों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि तिब्बत में आवासीय विद्यालयों की संख्या चीन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है और यह हाल के वर्षों में बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि तिब्बती आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण

स्कूलों को जबरन बंद करने और टाउनशिप या राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों में बदले जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। असल में टाउनशिप या राष्ट्रीय स्तर के स्कूल विशेष रूप से शिक्षण और संचार में चीनी भाषा का उपयोग करते हैं। इस कारण भी तिब्बत में आवासीय स्कूलों की संख्या बढ़ी है।

विशेषज्ञों ने तिब्बती शिक्षण, धार्मिक और भाषाई संस्थानों के खिलाफ शृंखलाबद्ध दमनकारी कार्रवाइयों के माध्यम से तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को हान वर्चस्व वाले चीनी बहुमत में 'जबरन विलीन' करने की चीनी नीति पर चिंता व्यक्त की। विशेषज्ञों ने तिब्बती भाषा और शिक्षा की वकालत करने वाले तिब्बती कार्यकर्ताओं के प्रति चीन के अनवरत उत्पीड़न पर भी ध्यान आकृष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि वे नवंबर २०२२ में चीन के साथ किए गए संवाद में उठाए गए उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में चीनी अधिकारियों के संपर्क में हैं।

प्रतिनिधि थिनले चुएक्यी ने कहा कि 'यह तिब्बत पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा जारी पहली प्रेस विज्ञप्ति में से एक है। इसमें तिब्बत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का विवरण दिया गया है और हम आशा करते हैं कि तिब्बत में गंभीर स्थिति को देखते हुए कई लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने बताया कि तिब्बत दुनिया में सबसे कम आजाद क्षेत्र है। जैसा कि विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि भले ही चीन के अन्य हिस्सों में कई आवासीय विद्यालय हैं, लेकिन तिब्बत में उनकी संख्या बहुत अधिक है। यह तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को नष्ट करने के चीन के ठोस और व्यवस्थित प्रयासों की ओर इशारा करता है। हम विशेषज्ञों से आह्वान

करते हैं कि वे चीन के साथ बातचीत कर इन तथाकथित आवासीय विद्यालयों को बंद करने और इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए दबाव डालें।

▶ सिक्योंग ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, तिब्बत बिल को लागू करने में समर्थन मांगा

tibet.net, ०८ फरवरी, २०२३

वाशिंगटन डीसी। उत्तरी अमेरिका में अपने कार्यक्रमों के तहत, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने वाशिंगटन डीसी में तिब्बत के कई प्रमुख समर्थकों और दोस्तों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की।

०७ फरवरी की सुबह सिक्योंग ने विनियोग पर हाउस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सांसद डियाज़ बलार्ट से मुलाकात की, उसके बाद महिला सांसद यांग किम और सीनेटर ब्रायन शाट्ज़ के साथ बैठक की।

इसके बाद सिक्योंग ने विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल टी. मैककॉल से मुलाकात की, जो प्रतिनिधि सभा में 'तिब्बत-चीन संघर्ष अधिनियम के प्रस्ताव' को फिर से प्रस्तुत करने वाले कांग्रेसियों में से एक हैं। इसी तरह, सिक्योंग ने सीनेटर टॉड यंग से मुलाकात की, जो द्विदलीय समूह में शामिल सीनेट के सदस्यों में हैं। इस समूह ने अमेरिकी सीनेट में उपरोक्त तिब्बत विधेयक पेश किया था।

सिक्योंग ने विधेयक को अधिनियमित करने में सीनेटरों और सांसदों से लगातार समर्थन का आग्रह किया। इस तरह का समर्थन यूरोपीय संघ और अन्य देशों के सांसदों से भी अपनी-अपनी संसदों में इसी तरह के बिल को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रोत्साहित करेगा। यह तब और उपयोगी साबित होगा, जब संबंधित संसदों की बैठकों के दौरान तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर राजनीतिक और वित्तीय समर्थन की मांग की जाएगी।

'इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी)' के अध्यक्ष रिचर्ड गेरे ने सिक्योंग के साथ बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्रतिनिधि डॉ नामग्याल छोडुप और आईसीटी के अंतरिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित थे।

सिक्योंग ने सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर अफेयर्स (डीआरएल) के निदेशक और कर्मचारियों और अध्यक्ष डेरेक मिशेल और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (एनडीआई) के कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उन्हें सीटीए के उपक्रम और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया।

▶ चीनी अधिकारियों ने ड्रैगो काउंटी में तिब्बतियों पर संचार प्रतिबंध लगाया

rfa.org/ सांगयाल कुंचोक, ०२ फरवरी, २०२३

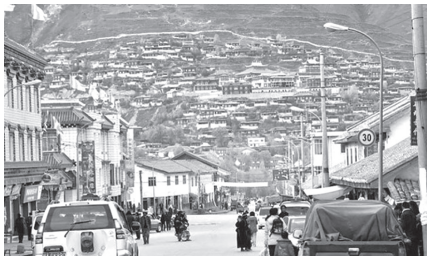

तिब्बत और चीन के अंदर की स्थिति की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि चीन ने चीनी शासन के प्रतिरोध का केंद्र रहे सिचुआन प्रांत की एक काउंटी के तिब्बती निवासियों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं।

क्षेत्र के सूत्रों ने कहा कि चीनी अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों को पददलित करने के लिए २०२१ से क्षेत्र में विशाल बुद्ध प्रतिमाओं का विध्वंस शुरू किया गया था और भिक्षुओं और स्थानीय निवासियों को इसे देखने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद ड्रैगो काउंटी में संचार पर प्रतिबंध लगाना नवीनतम उपाय है।

ड्रैगो काउंटी को चीनी में लुहुओ कहा जाता है और यह ऐतिहासिक तौर पर परंपरागत खाम तिब्बती प्रांत के सिचुआन प्रांत में कार्देज़ तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर में स्थित है।

सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करते हुए सूत्रों में से एक ने कहा, 'इस साल जनवरी की शुरुआत में ड्रैगो काउंटी में स्थानीय चीनी अधिकारियों ने क्षेत्र में रहने वाले तिब्बतियों को तिब्बत के बाहर के लोगों के साथ संचार संपर्क बंद करने की चेतावनी दी है।'

उन्होंने कहा, 'उनके सेल फोन बेतरतीब ढंग से जांचे जाते हैं और बाहर के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से मना किया जाता हैं। उन्हें देश से बाहर अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने या पैसे भेजने की भी अनुमति नहीं है।'

फ्री तिब्बत' और उससे संबद्ध अनुसंधान शाखा 'तिब्बत वॉच' द्वारा जनवरी में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों पर दमन तेज कर दिया है। उन्होंने ड्रैगो काउंटी में गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए महत्वपूर्ण धार्मिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया है।

तिब्बती बौद्ध स्थलों का विध्वंस ड्रैगो काउंटी में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख वांग डोंगशेंग के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिन्होंने पहले सिचुआन के विशाल लारुंग गार बौद्ध अकादमी में बौद्ध भिक्षुओं के निष्कासन और अकादमी के विध्वंस अभियान की कमान संभाली थी।

एक अन्य तिब्बती ने अपनी सुरक्षा के डर से पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया, 'जब से वांग डोंगशेंग को ड्रैगों में काउंटी प्रमुख

के रूप में नियुक्त किया गया है, तब से तिब्बतियों के खिलाफ अभियान बद से बदतर होता गया है।' उन्होंने आरएफए को बताया, 'बड़े पैमाने पर संचार पाबंदियां और अन्य सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों और मठों में रहने वालों को पुन:शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया है।'

२००८ के बाद से ड्रैगो काउंटी के निवासियों ने चीनी सरकार के खिलाफ विरोध- प्रदर्शनों में भाग लिया है। इस कारण चीनी अधिकारियों ने यहां हस्तक्षेप किया, जिसमें २००९ और २०१२ में बड़ी दमनात्मक कार्रवाई शामिल है।

▶ बीजिंग तिब्बत में अवज्ञा के किसी भी संकेत को अलगाववाद के कृत्य के रूप में देखता है और उसे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताता है। लिथांग काउंटी में हिरासत में राजनीतिक कैदी गेशे फेंडे ग्यालत्सेन की मौत

tibet.net०२ फरवरी, २०२३

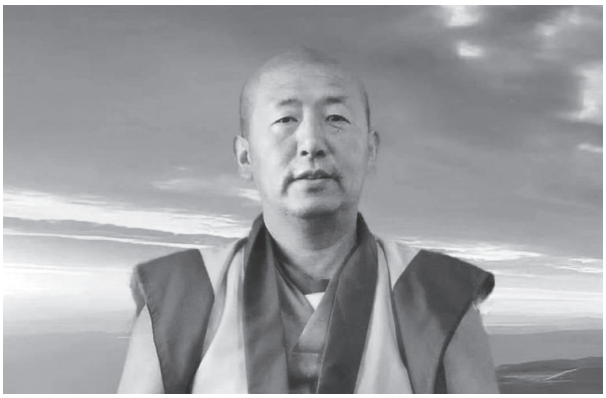

धर्मशाला। चीन के सिचुआन प्रांत में शामिल कर दिए गए कार्दजे तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर अंतर्गत लिथांग काउंटी के ग्योंगपा टाउनशिप निवासी ५६ वर्षीय प्रमुख तिब्बती भिक्षु की कथित तौर पर अज्ञात अस्वस्थता के कारण २६ जनवरी २०२३ को मृत्यु हो गई है। भिक्षु पिछले साल मार्च से पुलिस स्टेशन में हिरासत में बंद थे।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, गेशे फेंडे ग्यालत्सेन अक्सर अपने शिष्यों को धार्मिक शिक्षा देने में लगे रहते थे। वह लिथांग में शेडुब धारग्येलिंग मठ के जीर्णोद्धार में भी सक्रिय रूप से लगे हुए थे। मार्च २०२२ में उन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा काउंटी में दो पक्षों के बीच विवाद में मध्यस्थता करने पर मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और कारावास की सजा सुनाई गई। प्राधिकरण ने उनके शव को ग्योंगपा में उनके पैतृक शहर में तो पहुंचाया, लेकिन तीन दिनों के लिए आंतरिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को उनके अंतिम दर्शन से रोक दिया। कई दिनों के बाद शव को बीजिंग भेज दिया गया।

गेशे फेंडे ग्यालत्सेन का जन्म लिथांग काउंटी के ग्योंगपा टाउनशिप में हुआ था। वह १९८५ में बौद्ध तंत्र विद्या का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे और दक्षिण भारत के बाइलाकुप्पे में सेरा मे मठ के पोमरा खंगत्सेन में गेशे की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद, तिब्बत लौटने से पहले उन्होंने विद्वानों को तंत्र और ध्यान पर शिक्षा देने के लिए धर्मशाला, मनाली, दार्जिलिंग, भूटान आदि की लंबी आध्यात्मिक यात्राएं कीं।

▶ एनएचआरसी के ५२वां सत्र शुरू होने पर तिब्बत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ तिब्बतियों का प्रदर्शन

tibet.net, २८ फरवरी, २०२३

FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE

CHAIRMAN MCCAUL

जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५२वें सत्र के पहले दिन २७ फरवरी २०२३ को स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय ने चीनी सरकार की नीतियों के कारण तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने विरोध-प्रदर्शन किया।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के कार्यान्वयन पर चीन की हाल ही में समाप्त समीक्षा के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चीन से उसकी 'एकत्ववादी नीतियों' और तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में व्यापक अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठाया। लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करने के लिए आवासीय विद्यालयों की प्रणाली शुरू किए जाने की नीति ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को और चिंतित कर दिया है। आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य इन तिब्बती बच्चों को मूल चीनी नस्ल में विलीन करना भी है। चीन में, विशेष रूप से तिब्बत और चीनी सरकार के शासन के तहत अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद चीन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

सभा को संबोधित करते हुए तिब्बत ब्यूरो, जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चोएक्यी ने कहा कि 'तिब्बत एक अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण से चीनी सरकार द्वारा दशकों से तिब्बतियों के व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह समय है कि संयुक्त राष्ट्र तिब्बत पर ठोस

कदम उठाए और अपने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए चीनी सरकार को तिब्बत और चीनी सरकार के शासन के तहत अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराए। प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आगामी सत्र के दौरान तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति को उठाने का आह्वान किया।

लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा चोएक्यी ने गो शेरब ग्यात्सो और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामलों की याद दिलाया और उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की। स्विस-तिब्बती मैत्री संघ (फ्रांसीसी खंड) मार्गुराइट कॉन्टैट की प्रतिनिधि ने कहा कि चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में 'नस्ल संहार के द्वारा तिब्बतियों की पहचान को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की नीति' चल रही है। उन्होंने कहा कि वह स्विस संसद में तिब्बत में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगी।

▶ प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने विदेश, रक्षा, व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के सदस्यों से मुलाकात की

tibet.net १७ फरवरी, २०२३

कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई संसद के शरद सत्र की प्रक्रिया के बीच कैनबरा स्थित तिब्बत कार्यालय और ऑस्ट्रेलियाई तिब्बत परिषद ने संयुक्त रूप से १४ और १५ फरवरी को वहां के संसद भवन में विदेश, रक्षा और व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के सदस्यों से मुलाकात की और तिब्बत का अपना पक्ष रखा।

प्रतिनिधि कर्मा सिंगे और ऑस्ट्रेलियाई तिब्बत परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज़ो. बेडफ़ोर्ड ने सांसद मारिया वामवाकिनौ, सीनेटर लिंडा रेनॉल्ड्स, सांसद पीटर खलील और सीनेटर डेविड फ़ॉसेट के एक कर्मचारी जेनिस मैकशेन के साथ बैठकें कीं। उन्होंने तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय समूह के सह अध्यक्षों- माननीय सांसद वारेन एंशच, सांसद सुसान टेम्पलमैन, और सीनेटर जेनेट राइस से भी मुलाकात की।

ऑस्ट्रेलियाई सांसदों और अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने उन्हें तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि कैसे चीनी सरकार की नीतियां १० लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को परिवारों से अलग कर रही हैं और तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों में तिब्बती संस्कृति को अपने में विलीन कर रही हैं।

उन्होंने परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म प्रणाली में हस्तक्षेप करने की चीनी सरकार की मंशा, ग्रामीण तिब्बतियों को शहरों और कस्बों में जबरन भेजने और हाल ही में तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों के हनन को लेकर दो वरिष्ठ चीनी अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे उन चीनी अधिकारियों को अपनी निगरानी सूची में रखें, जो ऑस्ट्रेलियाई मैग्निट्स्की अधिनियम के तहत स्वीकृत मानवाधिकारों का तिब्बत में हनन कर रहे हैं।

उन्होंने विदेश, रक्षा और व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के उपरोक्त सदस्यों से अपील की कि वे तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेष रूप से तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों पर सुनवाई करें।

बैठक में प्रतिनिधि कर्मा और डॉ. ज़ो. के साथ सचिव ल्हावांग ग्यालपो और ऑस्ट्रेलिया- तिब्बत परिषद के डिजिटल प्रचारक सोनम ग्याल्त्सेन भी थे।

बैठकों के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सांसदों को परम पावन दलाई लामा पर लिखीं किताबें और माइकल वान वॉल्ट वान प्राग द्वारा लिखित 'तिब्बत ब्रीफ २०/२०' किताब भेंट कीं।

▶ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में 'तिब्बत-चीन संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने' के लिए तिब्बत विधेयक को फिर से पेश किए जाने का स्वागत किया

tibet.net, ०९फरवरी, २०२३

FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE

CHAIRMAN MCCAUL

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में फिर से पेश किए गए

तिब्बत विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए एक नीति बनाएगा। आत्मनिर्णय के इस अधिकार का प्रयोग करने की तिब्बतियों के अधिकार को वर्तमान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की नीतियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और यह कि तिब्बत और पीआरसी के बीच संघर्ष अनसुलझा है, और यह कि तिब्बत की कानूनी स्थिति अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्धारित की जानी बाकी है। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि आगे का एकमात्र रास्ता परम पावन के मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को अपनाना है, जो कि चीन के जनवादी गणराज्य के संविधान के ढांचे के भीतर तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता स्थापित करने के लिए सद्भावना और बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत पर आधारित है।

कांग्रेस सदस्य जिम मैकगवर्न, कांग्रेस सदस्य माइकल मैककॉल, सीनेटर जेफ मर्कले और सीनेटर टॉड यांग के प्रयासों की सराहना करते हुए सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कालोन नोर्जिन डोल्मा ने कहा, 'वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में द्विदलीय विधेयक को पुन: पेश किया गया है। इस बीच केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने उत्तरी अमेरिका में अपने कार्यक्रमों के अनुरूप वाशिंगटन डीसी में तिब्बत के कई प्रमुख समर्थकों और दोस्तों से मुलाकात की और बातचीत की।

०७ फरवरी की सुबह सिक्योंग ने विनियोग पर हाउस कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य सांसद डियाज़ बलार्ट से मुलाकात की, उसके बाद महिला सांसद यंग किम और सीनेटर ब्रायन शाट्ज़ के साथ बैठक की।

इसके बाद सिक्योंग ने विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल टी. मैककॉल से मुलाकात की, जो प्रतिनिधि सभा में 'तिब्बत-चीन संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देनेवाले कानून के प्रस्ताव' को फिर से पेश करने वाले सांसदों में से एक हैं। इसी तरह, सिक्योंग ने सीनेटर टॉड यंग से मुलाकात की, जो द्विदलीय सीनेटरों के समूह में शामिल हैं। इस समूह ने अमेरिकी सीनेट में इस तिब्बत विधेयक को पेश किया था।

सिक्योंग ने विधेयक को पारित कराने में सीनेटरों और प्रतिनिधियों से लगातार समर्थन की याचना की। यह विधेयक यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के सांसदों के लिए वहां की संसदों में इसी तरह के विधेयक को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण बन सकता है और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके साथ ही वहां की संसदों की बैठकों के दौरान तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर राजनीतिक और वित्तीय समर्थन की मांग उठाने की प्रेरणा मिल सकती है।

सिक्योंग के साथ बैठक में वर्चुअल रूप से इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष रिचर्ड गेरे ने भाग लिया। प्रतिनिधि डॉ. नामग्याल छोड्रुप और आईसीटी के अंतरिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिक्योंग के साथ बैठक में साक्षात शामिल थे।

सिक्योंग ने सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर अफेयर्स (डीआरएल) के निदेशक और कर्मचारियों और अध्यक्ष डेरेक मिशेल और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (एनडीआई) के कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उन्हें सीटीए उपक्रम और इसकी भविष्य की योजनाएं के बारे में अवगत कराया।

अमेरिकी कांग्रेस में इस विधेयक का फिर से पेश किया जाना मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से लंबे समय से अनसुलझे चीन-तिब्बत संघर्ष के समाधान के लिए अमेरिकी सांसदों की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है।

कालोन नोरज़िन डोल्मा ने कहा, 'अमेरिका द्वारा एकजुटता का ऐसा मजबूत प्रदर्शन तिब्बती लोगों के अमेरिका के न्यायपूर्ण नेतृत्व में विश्वास और भरोसे को पुष्ट करता है। यह हर जगह शांति, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए प्रयास करने वालों की रक्षा करने के अमेरिकी मूल्यों और उसे आगे बढ़ाने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।' इस विधेयक के प्रस्ताव ने तिब्बत के भीतर तिब्बतियों की उम्मीदों को निर्विवाद रूप से गहरा कर दिया है। जैसा कि हम कहते हैं कि वे लगातार गंभीर दमन के शिकार हैं।'

तिब्बत के मुद्दे के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका के दृढ़ और सतत समर्थन को स्वीकार करते हुए कालोन ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से 'तिब्बत-चीन संघर्ष के स्थायी समाधान को बढ़ावा देनेवाले' तिब्बत विधेयक पर आगे बढ़ने और इसे नीति बनाने में अपना प्रयास करने के लिए समर्थन की अपील की।

▶ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती रिनचेन ल्हामो ने सीटीए का दौरा किया

tibet.net, ०९ फरवरी, २०२३

धर्मशाला। भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती रिनचेन ल्हामो ने ०९ फरवरी की सुबह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और गंगचेन किशोंग परिसर से सटे मठों का दौरा किया।

नेचुंग और गाडोंग मठों की यात्रा के बाद श्रीमती रिनचेन ल्हामो ने अपनी सहयोगी के साथ निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया, जहां डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद कार्यवाहक सिक्योंग कालोन नोरज़िन डोल्मा ने भारत में

तिब्बती समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कशाग सचिवालय में अतिथि प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। बैठक में डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग, तिब्बती सांसद छेरिंग यांगचेन, कैबिनेट सचिव छेग्याल चुक्या ने भी श्रीमती रिनचेन ल्हामो के साथ भाग लिया।

प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती सर्वोच्च न्यायिक आयोग, तिब्बतन वर्क्स और आर्काइव्स के पुस्तकालय, तिब्बत संग्रहालय और अपर तिब्बती चिल्ड्रेन्स विलेज स्कूल का भी दौरा किया।

▶ सिक्योंग वाशिंगटन डीसी में एमेरिटस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सांसद जिम मैकगवर्न से मिले

tibet.net, १० फरवरी, २०२३

वाशिंगटन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ०८ फरवरी को कैपिटोल भवन में स्पीकर एमेरिटस नैन्सी पेलोसी और कांग्रेस के सदस्य जिम मैकगवर्न से मुलाकात की। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के अध्यक्ष रिचर्ड गेरे इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर की स्थिति, परम पावन दलाई लामा और सीटीए की तिब्बत मुद्दे को हल करने की योजनाओं के बारे में नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी दी। स्पीकर एमेरिटस पेलोसी और सांसद मैकगवर्न ने सिक्योंग को अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की।

सिक्योंग ने लंबे समय से तिब्बत समर्थक सांसद क्रिस्टोफर एच. स्मिथ से भी मुलाकात की। स्मिथ चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग (सीईसीसी) के अध्यक्ष हैं। बातचीत के दौरान, सिक्योंग ने उल्लेख किया कि इस विधेयक को अमेरिका में पारित करने से आयोग में तिब्बत पर संभावित सुनवाई के लिए यह यूरोपीय संघ के देशों को अपनी-अपनी संसदों में इसी तरह का विधेयक पेश करने के लिए उदाहरण बनेगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अभिनेता रिचर्ड गेरे ने आभासी रूप से बैठक में भाग लिया, जबकि प्रतिनिधि डॉ. नामग्याल चोएड्रुप और आईसीटी के अंतरिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सिक्योंग के साथ उपस्थित हुए।

▶ जापान के तिब्बत समर्थक समूह ने चीन को तिब्बती धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी

tibet.net, १३ फरवरी, २०२३

टोक्यो। जापान के तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों ने १३ फरवरी को पांच सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा चीन को तिब्बती धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई है। इसमें सर्वोच्च तिब्बती लामाओं, विशेष रूप से १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन शामिल है। प्रस्ताव में चीनी आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन शिक्षा देने की नीति को तत्काल वापस लेने का भी आह्वान किया गया है।

'सेव तिब्बत नेटवर्क' और जापान में तिब्बती समुदाय ने १३ फरवरी को ही संयुक्त रूप से ऑनलाइन समर्थक समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में १० प्रमुख समर्थक समूहों और २८ लोगों ने भाग लिया। इसमें अतिथि के तौर पर जापान के राष्ट्रीय और स्थानीय वकीलों और तिब्बत हाउस के प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

पूर्व संसद सदस्य और 'सेव तिब्बत नेटवर्क' के अध्यक्ष माकिनो सेशु ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और जापान में तिब्बत समर्थक नेटवर्क और स्वतंत्रता और न्याय के लिए तिब्बती संघर्ष के साथ अपने सहयोग की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अलावा, उन्होंने परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी बैठकों के बारे में बताया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कैसे सभी सदस्यों को काम करना चाहिए और परम पावन द्वारा बताए गए अहिंसक मार्ग का पालन करना चाहिए।

प्रतिनिधि डॉ. आर्य छेवांग ग्याल्पो ने आयोजकों, सांसदों और प्रतिभागियों को तिब्बत मुद्दे में उनकी रुचि और समर्थन के

लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यालय की गतिविधियों पर बात की और उन्हें तिब्बत में हो रही सांस्कृतिक क्रांति के दिनों जैसे अत्याचारों और धार्मिक प्रतीकों के अपमान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वकीलों और सदस्यों से तिब्बत में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन, धार्मिक उत्पीड़न और तिब्बती पहचान के उन्मूलन पर अधिक मुखर होने की अपील की। जापान के संसदीय तिब्बत समर्थक समूह के वर्तमान महासचिव इशिकावा अकिमासा और पूर्व महासचिव नागाओ ताकाशी ने क्रूर कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के रूप में तिब्बत मुद्दे के महत्व पर बात की। उन्होंने अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया और जापानी जनता को तिब्बत मुद्दे के बारे में शिक्षित करने में समर्थक समूह के सदस्यों के सहयोग का अनुरोध किया।

तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधियों ने समूहों की गतिविधियों के बारे में बात की और तिब्बती पहचान, धर्म और संस्कृति को मिटाने की चीनी नीति की निंदा की। उन्होंने चीन द्वारा धार्मिक मूर्तियों, प्रार्थना चक्रों और झंडों को नष्ट करने के कुकृत्यों के बाद लामाओं के अवतार के चयन पर अधिकार का दावा करने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग ने आयोजकों को उन्हें आमंत्रित करने के लिए

धन्यवाद दिया और तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के लिए सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया।

तिब्बत के लिए स्थानीय संसदीय समर्थक समूह के अध्यक्ष तागुची योशिनोरी और उपाध्यक्ष अरिसावा युमा ने तिब्बत मुद्दे के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए समर्थन समूह के सदस्यों को अपना समर्थन दिया और उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की।

अंत में सदस्यों ने पांच सूत्रीय प्रस्ताव पारित करने का संकल्प लिया।
ये संकल्प इस प्रकार हैं:-
हम जापान के तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधि और सदस्य १२ फरवरी, २०२३ को संकल्प लेते हैं और मांग करते हैं कि :-

१. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के नेतृत्व को तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और तिब्बतियों को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने देना चाहिए।
२. सीसीपी नेतृत्व को कम्युनिस्ट माहौल वाले आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन शिक्षा देना बंद करना चाहिए।
३. सीसीपी नेतृत्व को अल्पसंख्यक अधिकार कानून लागू करना चाहिए, जहां अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी भाषा का उपयोग करने और उसे संरक्षित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है।
४. नास्तिक सीसीपी नेतृत्व को तिब्बती धार्मिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए और दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन करने के अधिकार का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
५. हम जापान के तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधि और सदस्य सीसीपी नेतृत्व द्वारा नियुक्त किसी लामा या दलाई लामा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उनका विरोध करेंगे।

▶ तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह ने १० लाख तिब्बतियों को जबरन आत्मसात करने और अलग करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चिंता से सहमति जताई

tibet.net, १६ फरवरी, २०२३

जिनेवा। तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह ने तिब्बत में १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने और उन्हें अपने परिवार और समुदाय से अलग करने को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा जताई गई चिंता के सुर में सुर मिलाया है।

यह बयान संसदीय समर्थक समूह के सह अध्यक्षों- नेशनल काउंसिलर्स एंड्रिया गीसबुहलर, निक गुगर, फैबियन मोलिना, निकोलस वाल्डर और काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सदस्य और संसदीय समर्थक समूह की उपाध्यक्ष माया ग्राफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

बयान में कहा गया है, 'तिब्बत के लिए संसदीय समूह के सदस्य उस नीति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में बड़ी शिद्दत से चिंतित हैं जो तिब्बती बच्चों को किंडरगार्टन उम्र से चीनी शैली की आवासीय स्कूल प्रणाली में डालने को मजबूर करती है। जिसमें बच्चों या उनके माता-पिता के विरोध करने की कोई गुंजाईश नहीं है।'

नेशनल काउंसिलर और तिब्बत के लिए संसदीय समूह की सह-अध्यक्ष फैबियन मोलिना ने चेतावनी दी कि 'आवासीय स्कूल की यह प्रणाली तिब्बती बच्चों को सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप से चीनी नस्ल में विलीन हो जाने के लिए मजबूर करती है।'

नेशनल काउंसिलर और संसदीय समूह के सह-अध्यक्ष निकोलस वाल्डर कहते हैं, 'परिणामस्वरूप तिब्बती बच्चे अपनी मातृभाषा और तिब्बती भाषा में संवाद करना भूल रहे हैं, जो उनके विलीन हो जाने और उनकी अपनी तिब्बती पहचान के क्षरण में योगदान देता है।'

बयान में यह भी कहा गया है कि, 'ये अपरिहार्य आवासीय स्कूल तिब्बती संस्कृति और धर्म के खिलाफ अन्य दमनकारी उपायों की शृंखला का हिस्सा हैं।'

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुएक्यी ने तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह के बयान का स्वागत किया और उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

▶ चीन की प्रतिबंधात्मक नीतियां तिब्बत में लगातार जारी है

tibet.net, १६ फरवरी, २०२३

धर्मशाला। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत के अंदर दमनकारी नीतियों को सख्ती से लागू करना जारी रखे हुए है। वह तिब्बतियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का लगातार उल्लंघन करती है और उनके साथ विषमतामूलक व्यवहार करती है।

तिब्बत के अंदर के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह कहा जाता है कि स्नातक स्तर की शिक्षा पाए बहुत कम चुनिंदा तिब्बती छात्र तथाकथित 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं। जबकि बाकी मुख्य रूप से चीनी अधिकारियों के अधीन काम करने को मजबूर हैं। तिब्बतियों के लिए नौकरी के घटते अवसरों के कारण शिगात्से जैसे क्षेत्रों में १८ से ऊपर के अधिकांश

तिब्बती स्नातक पीएलए में भर्ती होने को मजबूर हैं। इसके अलावा, युवा तिब्बती छात्रों के ब्रेनवॉश करने के प्रयास में स्कूलों में शिक्षा को राजनीतिक प्रचार के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, जो परम पावन दलाई लामा के खिलाफ बार-बार आरोप लगाते हैं कि वह अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

इसी तरह कार्देज़ प्रान्त के पल्युल काउंटी की वार्षिक रिपोर्ट में तिब्बती बौद्ध धर्म के चीनीकरण के लिए प्राधिकारों द्वारा कानून का अनुपालन करते हुए धार्मिक मामलों की निगरानी में वृद्धि कर दी गई है। रिपोर्ट में आगे मठों से ४६५१ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के निष्कासन और पूर्वी तिब्बत के खाम में सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध संस्थानों में से एक यारचेन गार मठ में ४१२० भिक्षु आवासों के विध्वंस के बारे में उल्लेख किया गया है।

▶ संयुक्त राष्ट्र समिति का तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में एकत्ववादी नीतियों और व्यापक अधिकारों के उल्लंघन पर चीन से सवाल

tibet.net, १७ फरवरी, २०२३

जिनेवा। पिछले दो दिनों यानी १५-१६ फरवरी २०२३ के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की समिति ने तीसरी बार चीन द्वारा नियमों के कार्यान्वयन किए जाने की समीक्षा की। संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों ने तिब्बतियों, उग्यूरों, मंगोलियाई और अन्य लोगों को जबरन आत्मसात करने के लिए मजबूर करने वाली एकत्ववादी नीतियों के साथ-साथ तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान (चीनी: झिंझियांग), हांगकांग, मकाऊ और मुख्य भूमि चीन में किए जा रहे अधिकारों के व्यापक उल्लंघन पर चीन से सवाल किया है।

संयुक्त राष्ट्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद एज़ेल्डिन अब्देल-मोनीम ने समीक्षा-सत्र की अध्यक्षता की। समीक्षा करने वाली टास्क फोर्स में कंट्री रिपोर्टियर माइकल विंडफुहर, लुडोविक हेनेबेल, प्रीति सरन और असरफ अली काउन्हे शामिल थे। ३९ सदस्यों के चीनी सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में चीन के राजदूत और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में चीन के स्थायी प्रतिनिधि चेन जू ने किया।

संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों ने तिब्बतियों, उग्यूरों और दक्षिणी मंगोलियाई लोगों के खिलाफ चीन द्वारा लागू की गई एकत्ववादी-एकजातीय नीतियों पर बार-बार चीन से सवाल किया और कहा कि चीन की ये नीतियां स्पष्ट रूप से प्रतिकूल हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र समिति ने तिब्बत से संबंधित व्यापक विषयों पर चीन से सवाल किया। इनमें तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, तिब्बती खानाबदोशों का जबरन पुनर्वास, समायोजन और तिब्बतियों को उनकी भूमि से बड़े पैमाने पर विस्थापन, दानवाकार बांधों के निर्माण से पहले तिब्बतियों की जबरन सहमति प्राप्त करना, तिब्बत में जबरन श्रम, श्रम बाजारों में तिब्बतियों से भेदभाव, कार्यस्थल पर धर्म की स्वतंत्रता, तिब्बतियों के लिए शिक्षा में असमानता, आवासीय स्कूलों में लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों का जबरन नामांकन, तिब्बतियों के भाषा अधिकार, तिब्बतियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार (जिसमें प्रार्थना झंडे और पवित्र तीर्थों की परिक्रमा यानी कोरा शामिल है), और धार्मिक स्थलों का बड़े पैमाने पर विनाश, पुनर्जन्म के तिब्बती बौद्ध परंपरा को नियंत्रित करने के उपाय आदि शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों द्वारा डेटा और स्पष्टीकरण मांगने के विशिष्ट और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बावजूद चीनी प्रतिनिधिमंडल संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहा। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने या तो सभी आरोपों का खंडन किया या अपने पक्ष में बयान दिए। प्रतिनिधिमंडल के जवाब देने की असंतोषजनक प्रवृत्ति से चिढ़कर समिति के सदस्यों में से एक ने टिप्पणी की कि यदि चीनी प्रतिनिधिमंडल उल्लंघन के पुख्ता आरोपों को 'निराधार' मानता है तो उसे जांच का विवरण प्रदान करना चाहिए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा, इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत और तिब्बत एडवोकेसी गठबंधन के सदस्यों ने समीक्षा- सत्र में भाग लिया। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुएक्यी ने सभी प्रमुख क्षेत्रों को छूते हुए चीन की विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा, 'समीक्षा मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समिति के सदस्यों और सचिवालय के समर्पण और जुनून को दर्शाती है।'

प्रतिनिधि थिनले चुएक्यी ने टिप्पणी की 'तिब्बत में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन जगजाहिर है और इसके बावजूद चीन बार-बार समीक्षा में सबूतों से इनकार करता है। समय आ गया है कि तिब्बत में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए चीन को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा, समिति बैठक का समापन करते हुए हम आशा करते हैं कि चीन अपनी नीतियों पर आत्मनिरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तिब्बती, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलियाई, हांगकांग और मकाऊ के लोगों को वास्तविक सार्वभौमिक मानवाधिकारों की गारंटी दी जाए।

▶ यूरोपीय संघ ने तिब्बती राजनीतिक कैदियों की अविलंब रिहाई की मांग की

tibet.net, १८ फरवरी, २०२३

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ-चीन मानवाधिकार वार्ता के ३८वें दौर के दौरान गैरकानूनी हिरासत, जबरन गायब करने, यातना और दुर्व्यवहार के मामलों पर चिंता व्यक्त की और चीन से मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की जांच करने और इन उल्लंघनों को रोकने का आग्रह किया।

१७ फरवरी २०२३ को आयोजित एक दिवसीय बैठक में यूरोपीय संघ ने तिब्बतियों, उग्यूरों समेत धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों की कमजोर स्थिति पर प्रकाश डाला और गो शेरब ग्यात्सो, रिनचेन सुल्ट्रिम और ताशी दोर्जे सहित तिब्बती कार्यकर्ताओं, लेखकों और धार्मिक नेताओं की तत्काल रिहाई का आह्वान किया।

उन्होंने तिब्बती क्षेत्रों, पूर्वी तुर्किस्तान, भीतरी मंगोलिया और हांगकांग में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी चर्चा की।

वार्ता के अंत में यूरोपीय संघ द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया कि बातचीत में यूरोपीय संघ और चीन दोनों में मानवाधिकारों पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया गया। इसने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने मानवाधिकारों पर इस संवाद चैनल को फिर से शुरू करने का स्वागत किया।

प्रतिनिधि जेनखांग ने तिब्बती राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई का आह्वान करने और तिब्बत की स्थिति को लेकर चिंता जताने के लिए यूरोपीय संघ का स्वागत किया।

यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस में एशिया-पैसिफिक के उप प्रबंध निदेशक पाओला पंपलोनी और चीनी विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों के लिए उप महानिदेशक सुन लेई ने चीनी जनवादी गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया।

झिंझियांग में मानवाधिकारों के हनन में शामिल चीनी अधिकारियों के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों और यूरोपीय संसद के सदस्यों, अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ बीजिंग के जवाबी प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय संघ और चीनी सरकार के बीच मानवाधिकार वार्ता २०१९ से रुकी हुई है।

▶ दस लाख तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से जबरन अलग किया गया : संयुक्त राष्ट्र

bitterwinter.org /१५ फरवरी, २०२३

नवंबर में संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष दूतों ने चीन को लिखा। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया

मास्सिमो इंट्रोविग्ने

जब कनाडाई लोगों को पता चला कि बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर दिया जाता है और आवासीय स्कूलों में भेज दिया जाता है तो वहां विरोध की ज्वाला भड़क उठी और मुकदमों के मामले अचानक बढ़ गए। ये स्कूल अक्सर उनके माता-पिता से सैकड़ों मील दूर होते हैं, जहां उनकी संस्कृति और भाषा को मिटाकर एक नई, विदेशी पहचान देने की कोशिश की जाती है। कनाडा के ईसाई बोर्डिंग स्कूलों में स्वदेशी पहचान, भाषा और धर्म से वंचित फर्स्ट नेशन के बच्चों के साथ यही हुआ था।

हालांकि, प्रदर्शनकारी शायद इस बात से अनभिज्ञ थे कि जो कभी कनाडा में हुआ, वही आज चीन में चल रहा है और दस लाख तिब्बती बच्चे इसके शिकार हुए हैं।

तीन विशेष रिपोर्टियरों ने सबसे पहले चीन को दिनांक ११ नवंबर, २०२२ को एक गोपनीय पत्र लिखा। हालांकि वे कहते हैं कि वे चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क में बने रहे, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने पत्र और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

उनका दावा है कि तिब्बती लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप से आत्मसात करने के उद्देश्य से चीनी सरकार द्वारा लागू आवासीय स्कूल प्रणाली की नीतियों के कारण तिब्बती अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग दस लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के तीनों विशेष रिपोर्टियरों ने कहा कि वे इस बात से बहुत परेशान हैं कि हाल के वर्षों में तिब्बती बच्चों के लिए अनिवार्य आवासीय विद्यालय प्रणाली बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विपरीत कार्य करती है। इसका उद्देश्य तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में विलीन कर लेना है।

दस लाख तिब्बती बच्चों यानी तिब्बत के अधिकांश बच्चों को उनके माता-पिता के विरोध के बावजूद जबरन अलग कर दिया गया है और तिब्बत और चीन के दूर-दराज के स्थानों में आवासीय स्कूलों में भेज दिया गया है। वहां का 'शैक्षिक सामग्री' और माहौल बहुसंख्यक हान संस्कृति वाला है। इसमें पाठ्य-पुस्तक की सामग्री, विशेष रूप से मंदारिन चीनी (पुटोंघुआ) भाषा का उपयोग करते हुए, लगभग पूरी तरह से हान छात्रों के अनुभव को दर्शाती है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टियरों ने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप तिब्बती बच्चे अपनी मूल भाषा से दूर होते जा रहे हैं और तिब्बती भाषा में अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ आसानी से संवाद करने की क्षमता खो रहे हैं। यह उनकी पहचान को आत्मसात करने और पहचान को खत्म करने की राह को आसान करता है।

तिब्बती ग्रामीण स्कूल जो शिक्षण की भाषा के रूप में तिब्बती का उपयोग करते थे, अब बंद हो गए हैं। विशेष रिपोर्टियरों ने आगे कहा कि इन ग्रामीण स्कूलों को टाउनशिप या काउंटी स्तर के स्कूलों में बदल दिया गया है जो विशेष कर शिक्षण और संचार के लिए लगभग पुतोंगहुआ का उपयोग करते हैं और आमतौर पर बच्चों को इसे समझने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

इस नीति के उद्देश्य को लेकर विशेष रिपोर्टियरों को कोई भ्रम नहीं है। यह तिब्बतियों की अगली पीढ़ी का हान चीनी संस्कृति में 'पूरी तरह आत्मसात' करने और उनकी तिब्बती सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विरासत को मटियामेट कर देना भर है। कई अन्य लोगों ने इसे सांस्कृतिक संहार का नाम दिया है।

▶ स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल ने स्पेनिश सांसदों द्वारा 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' के गठन पर आभार व्यक्त किया

tibet.net, १७ फरवरी, २०२३

धर्मशाला। स्पेन की सीनेट में 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' समूह की स्थापना के बाद निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल ने आज १७ फरवरी को सीनेटर और समूह के अन्य सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए स्पेनिश सीनेटर रॉबर्ट मसीह नाहर को पत्र लिखा।

स्पीकर ने लिखा, 'स्पेन में फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत समूह की स्थापना के बारे में जानकर हमें खुशी हुई है और यह भी कि समूह का उद्घाटन तिब्बती नव वर्ष २१ फरवरी २०२३ को होगा।'

'मैं आपको और समूह के सभी सदस्यों को तिब्बतियों और निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि इस नए समूह के साथ हम स्पेन में तिब्बत के न्यायोचित मुद्दे के लिए सहयोग कर सकते हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य का समर्थन हमारे लिए मूल्यवान है।'

▶ स्पेनिश सीनेट में तिब्बत के लिए पहला अंतर-संसदीय समूह गठित

tibet.net २३ फरवरी, २०२३

मैड्रिड। ऐतिहासिक रूप से पहली बार स्पेनिश सीनेट में २१ फरवरी २०२३ को तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया। यह सर्वदलीय २९ सीनेटरों का समूह है।

समूह के गठन का उत्सव मनाने के लिए सीनेट के मैनुअल जिमेनेज़ अबाद हॉल में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्पेन में तिब्बती समुदाय की अध्यक्ष रिंगजिंग डोल्मा, यूरोप और अफ्रीका में निर्वासित तिब्बती संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले तिब्बती सांसद प्रतिनिधि जेनखांग, आदरणीय थुप्टेन वांगचेन और थुप्टेन ग्यात्सो भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

अपनी ब्रीफिंग में अंतर-संसदीय समूह के अध्यक्ष रॉबर्ट मसीह नाहर ने तिब्बती मुद्दे की व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्यों का वर्णन किया, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से तिब्बत में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान प्रकट करना, तिब्बत के अनसुलझे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना, यूरोपीय देशों में अन्य अंतर-संसदीय तिब्बत समूहों और यूरोपीय संसद में तिब्बत इंटरग्रुप के साथ मिलकर काम करना और तिब्बती मामलों के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति के आह्वान का समर्थन करने के लिए जनादेश के साथ परम पावन दलाई लामा और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतों के बीच ठोस बातचीत को शुरू कराना और बढ़ावा देना है।

सीटीए के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपने वीडियो संदेश में स्पेनिश सीनेट में तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह के गठन का स्वागत किया और सीनेटरों को भविष्य में धर्मशाला आने का निमंत्रण दिया।

तिब्बत कार्यालय की ओर से प्रतिनिधि जेनखांग ने इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत किया और समूह के अध्यक्ष तथा अन्य २८ सीनेटरों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने सामान्य रूप से तिब्बत की स्थिति पर एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुति दी। साथ ही सर्वाधिक महत्व वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला।

प्रतिनिधि जेनखांग ने आगे कहा, 'तिब्बत के इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण समय में तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह की स्थापना करना उन साठ लाख तिब्बतियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में जबरदस्त पीड़ा से गुजर रहे हैं। यह परम पावन दलाई लामा द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के लिए आपके समर्थन और बातचीत के माध्यम से चीन-तिब्बती संघर्ष को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।'

तीन अन्य तिब्बती वक्ताओं ने भी तिब्बत में स्थिति की गंभीरता को याद किया और समूह की स्थापना में उनके समर्थन के लिए सीनेटरों की सराहना की और निरंतर समर्थन का आग्रह किया।

पिछले साल वाशिंगटन डीसी में तिब्बत पर विश्व सांसदों के आठवें सम्मेलन में सीनेटर नाहर की भागीदारी के बाद उनकी भागीदारी का अगला तार्किक कदम इस समूह की स्थापना था। तिब्बत कार्यालय, ब्रसेल्स तभी से सीनेटर नाहर के निकट संपर्क में बना हुआ है।

तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह के शुभारंभ में लगभग ३५ सीनेटरों और पत्रकारों ने भाग लिया। प्रतिनिधि जेनखांग ने समूह के प्रत्येक सदस्य को पारंपरिक तिब्बती खटक, तिब्बती ध्वज की एक पिन और स्पेनिश में अनूदित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ एक डोजियर भेंट किया। उद्घाटन समारोह नए समूह के सदस्यों के सम्मान में तिब्बत कार्यालय, ब्रसेल्स द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन के साथ समाप्त हुआ।

▶ भारत के माननीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में समयलिंग बस्ती में लोसार समारोह की अध्यक्षता की

tibet.net, २७ फरवरी, २०२३

नई दिल्ली। तिब्बती नव वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली स्थित तिब्बत ब्यूरो कार्यालय, सेटलमेंट कार्यालय और संबंधित भारतीय कार्यालयों ने समारोह का आयोजन किया। भारत के माननीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में मुख्य अतिथि क्याबजे योंगज़िन लिंग छोक्लुल रिनपोछे थे। विशेष अतिथि सुरक्षा विभाग के कार्यवाहक सिक्योंग कालोन ग्यारी डोल्मा थे। इसके अलावा भारत-तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक श्री इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रिनचेन ल्हामो, श्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महानिदेशक श्री अभिजीत हलदर और अन्य उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि श्री किरेन रिजिजू ने लोसार में एकत्रित होने वाले तिब्बतियों के कल्याण की कामना की और परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व की सराहना की। परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती अच्छे आचरण का पालन करते हैं और भारत भूमि के कानूनों का पालन करते हैं और परम पावन की शांति की वकालत करते हैं, जिसकी दुनिया भर के लोग सराहना करते हैं। .

विशिष्ट अतिथि क्याब्जे योंगज़िन लिंग छोक्लुल रिनपोछे ने तिब्बतियों को अपने दैनिक जीवन में परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन का पालन करने की सलाह दी।

सुरक्षा विभाग के कार्यवाहक सिक्योंग कालोन ग्यारी डोल्मा ने तिब्बती पुनर्वास नीति- २०१४ को पारित कराने में भूमिका के लिए किरेन रिजिजू को धन्यवाद दिया और मामले पर उनसे निरंतर समर्थन की अपील की।

बीटीएसएम संरक्षक इंद्रेश कुमार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रिनचेन ल्हामो ने तिब्बतियों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और उन्हें तिब्बतियों को निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया।

इसी प्रकार प्रतिनिधि लोबसांग सांगेय ने परम पावन दलाई लामा के दीर्घायु और तिब्बतियों के सद्भाव के लिए अपनी शुभकामनाएं और प्रार्थना व्यक्त की।

▶ बीटीएसएम की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गाजियाबाद के कैलाश-मानसरोवर भवन में संपन्न

tibet.net, ०६ फरवरी २०२३

नई दिल्ली। भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ०४ और ०५ फरवरी २०२३ को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश-मानसरोवर भवन में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मंच के मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार ने की।

बैठक के उद्घाटन सत्र में देश भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बीटीएसएम के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया में चीन जैसे धोखेबाज देश का पर्दाफाश करने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता की जरूरत है। मुझे खुशी है कि भारत-तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ जनजागरण का कार्य कर रहे हैं।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन एक ऐसा देश है जिसे इंसानियत से कोई लेना-देना नहीं है। यह दुनिया के कई देशों को किसी न किसी रूप में टेंशन देता रहता है। चीन से मानवता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि ०५ मई २०२३ को भारत-तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना के २५ साल पूरे होने वाले हैं और उसी दिन से फोरम का 'रजत जयंती वर्ष' शुरू होगा। रजत जयंती वर्ष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से होगी और समापन भी ०५ मई २०२४ को धर्मशाला में ही होगा। इस बीच पूरे देश में तिब्बत के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तिब्बती मुद्दे को मजबूत करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस उद्घाटन-सत्र में निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य येशी फुंटसोक और राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर स्वामी डॉ. अभिजीतानंद जी महाराज ने भी विचार व्यक्त किए।

मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उद्घाटन-सत्र में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि तिब्बत को मुक्त कराने के मिशन के रूप में माननीय इंद्रेश जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को हमें पूरा करना है।

आईटीसीओ की समन्वयक ने वी-टैग, सीटीए के डीआईआईआर द्वारा

शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान पर प्रकाश डाला जो तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों को बंद करने से संबंधित है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से याचिका पर हस्ताक्षर करने और इसे अन्य सदस्यों के पास भेजने की अपील की।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग की कालोन ग्यारी डोल्मा, भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती रिनचेन ल्हामो, डॉ. इंद्रेश कुमार और भारत-तिब्बत सहयोग मंच के अन्य कार्यकारी सदस्य शामिल हुए।

सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमें हर स्तर पर सतर्क रहकर चीन के नापाक मंसूबों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को और गति देनी है। हम सबको संकल्प लेकर कैलाश-मानसरोवर के पवित्र जल को हर जिले में पहुंचाना है और चीन को कड़ा संदेश देना है कि कैलाश-मानसरोवर मुक्त होकर रहेगा। साथ ही तिब्बत की आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की जरूरत है।

कालोन ग्यारी डोल्मा ने सत्र को संबोधित करते हुए भारत-तिब्बत सहयोग मंच, इसके कार्यकारी सदस्यों और इसके सभी सदस्यों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और सभी तिब्बतियों की ओर से तिब्बत और तिब्बतियों के लिए अथक समर्थन और काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत-तिब्बत सहयोग मंच के २५ वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और तिब्बत और तिब्बतियों के लिए मंच से निरंतर समर्थन की अपेक्षा व्यक्त की।

श्रीमती रिनचेन ल्हामो ने सत्र में अपने संक्षिप्त संबोधन में भारत-तिब्बत सहयोग मंच को अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया और तिब्बत और तिब्बतियों के लिए मंच के काम और समर्थन के बारे में जानकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने मंच को उनके प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देने की बात कही।

डॉ. के.सी. अग्निहोत्री, श्री राजू और श्री चंद्रेश अग्रवाल ने भी समापन-सत्र को संबोधित किया।

अंत में मंच के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज गोयल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने एवं रजत जयंती वर्ष को जन-जन के बीच चर्चा का विषय बनाने के लिए क्षेत्रों और विभागों के अनुसार आयोजित बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई। भारत-तिब्बत सहयोग मंच के सभी सदस्यों ने माननीय इंद्रेश कुमार जी की तिब्बत को मुक्त कराने की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का संकल्प लिया।

स्थानीय जनता को तिब्बत के प्रति जागरूक करने के लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जन प्रतिनिधियों द्वारा भारत माता की जय, वन्दे मातरम, जय भारत और जय तिब्बत के नारों के साथ जागरूकता यात्रा भी निकाली गई।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंत में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संरक्षक डॉ. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर मोहन लाल, चंद्रशेखर साहू, स्वामी दिव्यानंद महाराज, राष्ट्रीय मंत्री नीरा शास्त्री, शिवकांत तिवारी, विजय शर्मा, रामकिशोर पासारी, नर्सिंग मेंगजी, श्री प्रमोद गोयल, श्री अनिल मोंगा और देश भर के ३५० प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

दो दिवसीय बैठक में भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय की प्रभारी समन्वयक ताशी देकी और कर्मचारी, तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोनपो धुंडुप, उपाध्यक्ष छेरिंग चोम्फेल और तिब्बती महिला संघ की उपाध्यक्ष छेरिंग डोल्मा ने भी भाग लिया।

▶ चीन ने तिब्बती नववर्ष समारोह में बौद्ध ध्वज फहराने पर रोक लगाई, आयोजक को हिरासत में लिया और जुर्माना लगाया

tibet.net, ०८ फरवरी, २०२३

स्रोत: तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी)

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत विश्वविद्यालय के एक छात्र को तिब्बती नववर्ष 'लोसार' पर समारोह आयोजित करने के लिए हिरासत में लिया और जुर्माना लगाया। समारोह के मंच पर पृष्ठभूमि में चीनी ध्वज के बजाय बौद्ध ध्वज प्रदर्शित किए गए थे।

टीसीएचआरडी को मिली जानकारी में पुष्टि की गई है कि तिब्बती छात्र गेफेल को २४ जनवरी की शाम को परंपरागत अमदो तिब्बती प्रांत और नए सिचुआन प्रांत के न्गाबा (चीनी : अबा) तिब्बती और क्वांग स्वायत्त प्रिफेक्चर के ज़ुंगचू (चीनी: सोंगपैन) काउंटी में मुगे टाउनशिप स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया।

गेफेल पर ५०,००० युआन का जुर्माना लगाया गया और २६ जनवरी की दोपहर को रिहा होते समय हर हफ्ते 'राजनीतिक शिक्षा' सत्र में भाग लेने का आदेश दिया गया।

मुगरे स्थित तिब्बती विश्वविद्यालय के छात्र तिब्बती सोनम लोसार के हर तीसरे दिन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह समारोह तिब्बत के कुछ हिस्सों और हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध समुदायों में मनाया जाता है।

कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गेफेल को 'चीनी राष्ट्र को विभाजित करने वाली गतिविधियों में शामिल होने' के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान गेफेल पर बौद्ध ध्वज प्रदर्शित करके कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया था जो अधिकारियों के अनुसार, तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज के समान था। गेफेल ने अधिकारियों को समझाया कि बौद्ध ध्वज शांति, करुणा और ज्ञान के सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक है और इसका राजनीति या राष्ट्र को विभाजित करने से कोई लेना-देना नहीं है।

लेकिन गेफेल को साप्ताहिक राजनीतिक शिक्षा सत्र में भाग लेने का आदेश दिया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों, जैसे कि चीनी झंडे का अनिवार्य उपयोग और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं के लिए भविष्य में चीनी भाषा का उपयोग करना आदि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

नए साल के कार्यक्रम में विशिष्ट कानून का उल्लंघन करने के लिए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। इन कानून उल्लंघनों में कार्यक्रम स्थल पर चीनी झंडे का उपयोग नहीं करना, स्थल को सजाने के लिए केवल तिब्बती अक्षरों का उपयोग करना, कार्यक्रम के दौरान किए गए सभी गीत और नृत्य तिब्बती भाषा में करना और कम्युनिस्ट पार्टी या चीनी सरकार की प्रशंसा करने वाले किसी भी प्रचार गीत को प्रदर्शित नहीं करना शामिल है।

तिब्बत में संपर्क रखने वाले एक सूत्र ने टीसीएचआरडी को बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में चीनी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता 'बेतुकी' थी, क्योंकि अधिकांश दर्शक स्थानीय तिब्बती खानाबदोश थे जो चीनी भाषा नहीं समझते हैं।

▶ भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु में 'फ्री तिब्बत: इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी एंड पीस इन एशिया' पर सेमिनार आयोजित किया

tibet.net, २७ फरवरी, २०२३

बेंगलुरु। माउंट कार्मल कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के सहयोग से भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने १४ फरवरी को 'फ्री तिब्बत: इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी एंड पीस इन एशिया (आजाद तिब्बत : भारतीय सीमा की सुरक्षा और एशिया में शांति)' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता थुप्टेन ग्यालत्सेन, ताशी वांगडू, एन. जयराम और कर्नल सतीश ने की।

दोनों निर्वासित तिब्बती- ग्यालत्सेन और वांगडू ने तिब्बत पर चीनी कब्जे, तिब्बतियों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रतिनिधियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति और विरासत के क्रमिक विध्वंस के बारे में बात की। ग्यालत्सेन ने कई तिब्बती परिवारों द्वारा अपने परिवार सहित अपने बच्चों को अवैध रूप से भारत भेजने में कई प्रकार के जोखिम के बारे में बात की। ग्यालत्सेन ने कहा, 'यह एक विश्वासघाती यात्रा है जहां आपका जीवन खतरे में है। लेकिन हम बच्चों की अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को साकार करने के लिए यह खतरा मोल लेते हैं। इसमें एक बार फिर से अपने परिवार से मिलने की लालसा तो हमेशा रहती है लेकिन यह डर भी बना रहता है कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे।'

वांगडू ने तिब्बत की संप्रभुता, निर्वासन में तिब्बती सरकार के गठन और तिब्बत को मुक्त करने के लिए उनकी लड़ाई का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने चीनी कब्जे पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोई कार्रवाई न करने की भी बात की। वांगडू ने कहा, 'दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सबसे अलोकतांत्रिक संस्था है, भले ही इसे लोकतंत्र की रक्षक संस्था माना जाता है। यह सब वीटो शक्ति के कारण है जिसका उपयोग चीन अपने दुश्मनों को वश में करने के लिए करता है।' उन दोनों ने जल युद्ध के बारे में बात की जिसे चीन ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ, उनकी अलगाववादी नीतियों और उनके प्रचार के खिलाफ छेड़ रखा है।

एक प्रसिद्ध पत्रकार जयराम ने चीन के सत्ता में उदय का संक्षिप्त इतिहास बताया। इनमें राजशाही का खात्मा, गणतंत्र का गठन, सीसीपी का जन्म, जनवादी युद्ध, सांस्कृतिक क्रांति और आर्थिक सुधार के बारे में बताया। उन्होंने हांगकांग पर चीनी आधिपत्य और हांगकांग में प्रत्यर्पण संधि के बारे में भी बात की, जिसके कारण अंततः कई लोगों की गिरफ्तारी और मौत हो गई। वहां पुलिस क्रूरता हुई और छात्रों और बुद्धिजीवियों को हिरासत में लिया गया। अंत में, कर्नल सतीश ने छात्रों को भारत में विभिन्न प्रकार की सीमाओं के बारे में शिक्षित किया जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों को विभाजित करती हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नोमेन्स लैंड आदि के बारे में बताया। उन्होंने उन विभिन्न सीमाओं के बारे में भी बात की जो भारत से लगती हैं। उन्होंने भारत के पड़ोसी और विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ सेना के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया। उन्होंने अवैध प्रवासन, नशीली दवाओं के व्यापार, बाड़ लगाने और रेशम मार्ग के विभाजन जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से बताया। कर्नल सतीश ने श्रोताओं को अर्धसैनिक बलों के प्रकारों और भारतीय सेना के शस्त्रागार में मौजूद तकनीकों के बारे में भी शिक्षित किया। कर्नल ने कहा, 'निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन युद्ध सबसे कुरूप व्यवसाय है और इसका कोई अंत नहीं है।'

संगोष्ठी का विषय संवेदनशील होने के बावजूद वक्ताओं ने अपने चुटीले हास्य से श्रोताओं को बांधे रखा। राजनीति विज्ञान के छात्रों के साथ-साथ अन्य विषयों के छात्रों ने भी इस सेमिनार में भाग लिया, जिससे सभागार खचाखच भरा हुआ था। यह आयोजन शैक्षिक था और दशकों से चल रहे मानवीय संकट के बारे में छात्रों को जागरूक करने में सफल रहा। इस तरह के आयोजन ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से तिब्बत के खामोश लोग अपनी कहानियां सुना सकते हैं। जैसा कि थुप्टेन ने कहा, 'तिब्बत से जो कहानियां आती हैं वे दुखद हैं, लेकिन मैं खुशी-खुशी उन्हें बताता हूं, क्योंकि इन कहानियों को अवश्य ही सुना जाना चाहिए।'

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com , coordinator@indiatibet.net

Febuary, 2023, Years: 44 Issue: 02 Regd No. : RNI 34636-79

स्पेनिश सीनेट में तिब्बत के लिए पहला अंतर-संसदीय समूह गठित

भारत तिब्बत सहयोग मंच के दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक।